

## **Iqta system:**

'Iqta' is an Arabic word denoting a sort of administrative regional unit. It is usually considered equivalent to a province.

Initially the Delhi Sultans had divided their empire into several 'Iqtas' or provinces or spheres of influence and put them under the charge of officers called 'Iqtadars' (governors).

The number of Iqtas was not fixed. There was no uniformity in their administration.

Besides 'Iqtadar', other names of the heads of an Iqta' was Naib Sultan, 'nazim' might' or 'wali'.

Each 'Iqta' was under the charge of an experienced general who generally was the

member of the royal family or a notable 'Amir' (noble) and confidant of the Sultan.

### **Duties and powers of the Iqtadar:**

1. He was under the supervision of the Central government and carried on orders of the Sultan.
2. He enjoyed the same powers in the province as the Sultan enjoyed in the empire.
3. He maintained large armies and was required to send the same when asked by the Sultan.
4. He maintained order in the territory under his charge and protected the life and property of the people.
5. He appointed soldiers in his army.

6. He collected revenue from the people of his territory.

7. From the revenue thus collected he administered expenditure on the maintenance of his army, his pay and other administrative expenditure and deposited the rest in the state treasury.

8. He sent yearly report of his income and expenditure to the centre.

### **Restrictions on the Iqtadar:**

1. The Iqtadar did not always enjoy hereditary powers. The Sultan could take back Iqta from him whenever he pleased.

2. The Iqtadar was liable to be transferred from

one place to another.

3. He could not engage himself in wars of extension without the prior approval of the Sultan.

4. He was required to send a part of the booty to the Sultan.

5. The elephants and the members of the royal family captured during wars were to be sent to the Sultan.

6. He was not allowed to hold his own court.

7. He could not use a canopy or royal emblem.

8. He could not mint coins in his name.

9. He could not read 'Khutba' in his name.

During the rule of a weak Sultan, the 'Iqtadars' were tempted to enjoy more powers. They even kept elephants an exclusive privilege of the Sultan.

### **Two categories of Iqtas:**

During the reign of Ala-ud-Din, the Iqtas were divided into two categories:

(1) Iqtas which had been under the Delhi Sultans from the very beginning

(2) The territories brought under control by Ala-ud-Din Khalji.

The 'muqtis' or the 'walis' i.e. the 'Iqtadars' of the second category were given more powers so that the newly acquired territories could be brought about under more effective control.

Besides the 'Iqtadar', there were several other officers of the central government.

The efficient functioning of an 'Iqta' depended on the power of the Sultan on the one hand and on the other hand on the capability of the 'Iqtadar'.

### **Division of 'Iqtas' into units:**

In due course the 'Iqtas' were divided into smaller units called 'shiqqs' 'parganas' and the villages.

The head of a 'Shiqq' was called 'Shiqqdar'. Important officials of a 'paragana' were the 'amil' or 'munsif' the treasurer and the 'qanungo'.

## **Local administration:**

The village, the smallest unit of administration was administered by local hereditary officers and the 'Panchayat' of the village. The 'Panchayat', looked after education, sanitation etc. It also acted as a judicial body.

The 'Chaudhri' the 'Patwari', the 'Khut' the 'Muqaddam' and the 'Chankidari' were the hereditary officers of the village who helped in the collection of revenue.

The Sultan or the governor or officials of the state normally did not interfere in the village administration.

## इकता व्यवस्था

इकता एक अरबी शब्द है। निजामुलमुल्क तुसी के रियासतनामा में इकता को परिभाषित किया गया है। गौरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इकता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गौरी ने 1191 ई. में ऐबक को हाँसी का इकता प्रदान किया। उसी ने मलिक नसीरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश इकता के रूप में प्रदान किया। माना जाता है कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक का क्षेत्र इकता के रूप में विभाजित कर दिया। इकता की दो श्रेणियाँ होती थीं। पहला, खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की इकता तथा दूसरा, कुछ गाँवों के रूप में छोटी इकता। गाँव के रूप में छोटी इकता खालसा का ही एक अंग होती थी।

इकतादार और सुल्तान के सम्बन्ध परिस्थिति पर निर्भर करते थे। अर्थात् इकतादारों की स्थिति तीन प्रकार की हो सकती थी। प्रथम प्रकार के इकतादार वे थे जिन्हें जीते हुये प्रदेश में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। दूसरे प्रकार के इकतादार वे थे जो अध्विजित क्षेत्र में नियुक्त किये जाते थे और उन्हें उस क्षेत्र को पुनः जीतना



होता था। ऐसे इक्तादारों पर सुल्तान की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती थी और तीसरे प्रकार के इक्तादार वे होते थे जो ऐसी भूमि पर इक्तादार नियुक्त किये जाते थे जो अभी तक जीता नहीं गया होता था और वैसे इक्तादार व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र होते थे।

इक्ता के प्रशासक मुक्ति या वलि कहलाते थे। ये सम्बन्धित क्षेत्र में भू-राजस्व का संग्रह करते थे और उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि प्रशासनिक खर्च और वेतन को पूरा करने के पश्चात् जो शेष रकम बचती है उसे वे केन्द्रीय खजाने में भेज दें और ऐसी रकम फवाजिल कहलाती थी। समय-समय पर कुछ के सुल्तानों द्वारा इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गयी। सुल्तान और मुक्ति का परस्पर सम्बन्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता था। सैद्धांतिक रूप में मुक्ति या वाली का पद वशानुगत नहीं होता था और साथ ही हस्तांतरणीय होता था। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति किया, वह इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिल्जी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया ताकि निहित स्वार्थ पैदा नहीं

हो सके। उसने इक्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त दीवान-ए-बजारत को यह अधिकार दिया गया की वह प्रत्येक इक्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। इक्ता के राजस्व में से इक्तादार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन में स्पष्ट विभाजन किया गया और ऐसा गयासुद्दीन तुगलक ने किया। मुहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा कदम उठाया। उसने भू-राजस्व संग्रह और प्रशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया। अब मुक्ति के अतिरिक्त एक और अमीर नियुक्त किया गया। वह प्रशासन का कार्य देखता था।

इक्ता के आय-व्यय के निरीक्षण के लिये एक आमील नामक अधिकारी भी नियुक्त होने लगा। मुहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के सैनिकों का वेतन भी केन्द्रीय खजाने से देने का प्रावधान किया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उसके इस कदम के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुयी और यही वजह है की उसके काल में इतने विद्रोह हुए। फिरोज तुगलक ने बिन मुहम्मद की नीति को उलट दिया और इक्तादार के पद को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें गाँव प्रदान करने

लगा और ऐसे गाँव वजह कहलाते थे और वजह को धारण करने वाले की वजहदार कहा जाता था। लोदियों के समय भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस काल में इक्तादारों का स्थानांतरण नहीं हो पाता था।